

प्रेषक,

ओम प्रकाश

सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियां,

उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं घीनी अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 31 मार्च 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 205/XXVII (1) / 2009 दिनांक 25.3.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के पारित लेखानुदान (1 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009 तक) के क्रम में सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित वचनबद्ध मदों में कुल धनराशि ₹ 820 (रुपये आठ लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-18

2425-सहकारिता आयोजनेत्तर

001-निदेशन तथा प्रशासन

(धनराशि हजार ₹ 0 में)

05- सहकारी न्यायाधिकरण

01-वेतन	500
02-मजदूरी	10
03-महगाई भत्ता	110
06-अन्य भत्ते	55
09-विद्युत देय	03
10-जलकर/जलप्रभार	03
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	02
13-टेलीफोन पर व्यय	17
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	03
योग:-	820

(रुपये आठ लाख बीस हजार मात्र)

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापूर्तिपत्र के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति एवं आपरेशनता है। उनमें व्यय करने के पहले एसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी०एम० 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के वित्तव्ययता सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के सज्ञान में लाया जाय।

6. इस सम्बन्ध वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 25.03.2009 में उल्लिखित किन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर सूचित करें।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता आयोजनेतर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05- सहकारिता न्यायाधिकरण के सुसंगत इकाईयों के नामे खाला जायेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)  
सचिव।

संख्या 302/XIV-1/ 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ-कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फ़ाइल हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनुसचिव।